

एक हजार एकड़ जमीन पर बनेगा डेटा सेंटर क्लस्टर

■ रामेन्द्र प्रताप सिंह

लखनऊ। लखनऊ और उन्नाव के बीच करीब 1000 एकड़ जमीन पर बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर के विकास की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने संबंधित जमीन, बिजली, पानी और फाइबर नेटवर्क समेत तमाम सुविधाओं की मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत से विस्तृत जानकारी मांगी है। प्रस्तावित क्लस्टर में करीब एक गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर विकसित किया जाना है।

स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज



■ लखनऊ और उन्नाव में उपलब्ध सरकारी व अधिग्रहीत जमीन का ब्योरा मांगा

कुमार सिंह ने लखनऊ और उन्नाव में उपलब्ध सरकारी व अधिग्रहीत जमीन का ब्योरा मांगा है। इसमें एक-दूसरे से सटे ऐसे भूखंडों की पहचान करने को कहा है, जिन्हें डेटा सेंटर

20 एमएलडी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए 20 एमएलडी पानी की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जलाशयों से निकाले जा सकने वाले पानी, पाइपलाइनों, पानी की गुणवत्ता के साथ उपचारित एसटीपी पानी की उपलब्धता व क्षमता का भी ब्योरा मांगा गया है। यानी डेटा सेंटर के लिए एसटीपी के पानी के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।

निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन जमीनों की जीआईएस लोकेशन, अक्षांश-देशांतर, स्थलाकृति, ऊंचाई, जल निकासी, मिट्टी और भू-तकनीकी स्थिति का भी

चार कैरियर से जुड़ेगा फाइबर नेटवर्क

लखनऊ-उन्नाव क्षेत्र में एयरटेल, बीएसएनएल, टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो, रेलटेल समेत दूरसंचार कंपनियों के फाइबर रूट, डक्ट और पॉप की जानकारी जुटाई जाएगी। क्लस्टर को तीन-चार अलग-अलग कैरियर और दो-तीन विविध मार्गों से जोड़ा जाएगा।

अध्ययन होगा। डाटा सेंटर के लिए अमेरिकन कम्पनी बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) का चयन किया गया है। कम्पनी के प्रतिनिधि सुधांशु चावला के नेतृत्व में टीम निरीक्षण

सबस्टेशन की क्षमता भी परखी जाएगी

यूपीपीटीसीएल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम समेत संबंधित बिजली कंपनियों से सबस्टेशन की क्षमता, ट्रांसफार्मर, पिछले तीन वर्षों का लोड और ग्रिड रिपोर्ट मांगी गई है। नए सबस्टेशन की लागत, बिजली पहुंचाने में लगने वाला समय और भविष्य की अतिरिक्त क्षमता का आकलन होगा।

करेगी। उन्होंने यूपीएसआईडीए, यूपीईडा, एलडीए, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण समेत संबंधित संस्थाओं को शीघ्र जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है।